

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2020 (उदयपुर डिक्री)

1. भैरूसिंह पिता श्री रणजीतसिंह राव, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. किशनसिंह पिता श्री रणजीतसिंह राव, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. श्रीमती गंगा पत्नी श्री दलीचन्द सोनी, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. उप पंजीयक, पंजीयक कार्यालय, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. पटवारी, पटवार हल्का बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
 काश्त0 अधि0-1955 विरुद्ध निर्णय
 व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली
 दिनांक 15.11.2019, प्र.सं. 29/12

---/---

- उपस्थित(वक्तबहस)
- 1- श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक अपीलान्तगण
 - 2- श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1
 - 3- श्री कमलेश चौहान राजकीय अभि.रे.सं. 2, 3, 4

---::---

निर्णय

दिनांक 09-11-2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्तगण द्वारा रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आसोलियों की मादड़ी में आराजी नंबर 377 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि



स्थित है, जिसके पुराने आराजी नंबर 608/2 थे जो पूर्व में प्रताबसिंह कशोरसिंह पिता नहारसिंह राव के नाम अंकित थी। उक्त खातेदार परताबसिंह व कशोरसिंह द्वारा वादीगण के दादा गोविन्दसिंह एवं मेगसिंह को संवत् 2012 महा विद 15 को 136/- रूपये में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार वाद वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से पर वादीगण का 60 वर्षों से अधिक समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, जिससे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादीगण खातेदार हो चुके हैं। अतः वाद वर्णित आराजी नंबर 377 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा के 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया तथा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर वादीगण का वाद खारिज करने की प्रार्थना की।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 15-11-2019 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 28-01-2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। वकील अपीलान्त द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्त द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रथम बार दिनांक 15-11-2019 को हुई। तत्पश्चात नकले प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। अतः मियाद कण्डोन की जावे। तार्ड में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत करने में अल्प विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अंकित किया कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दस्तावेज की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत साक्ष्य में ग्राह्य है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि अपीलान्ट को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपीलान्ट/वादीगण द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने असल दस्तावेज के अभाव में अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो विधि अनुकूल होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादीगण के अधिवक्ता को असल दस्तावेज प्रस्तुत करने के कई अवसर दिये गये, किन्तु इसके बावजूद भी वादीगण के अधिवक्ता द्वारा असल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दिनांक 26-07-2017 को 500/- की कोस्ट पर अंतिम अवसर दिया गया। इसके बावजूद भी 3 पेशियों तक अधिवक्ता वादीगण द्वारा असल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 11 नियम 21 सी.पी.सी. के तहत वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15-11-2019 यथावत रखी जाती है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 09-11-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासएम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

भैरूसिंह पिता रणजीतसिंह राव, बनाम श्रीमती गंगा पत्नी दलीचन्द सोनी,
निवासी आसोलियों की मादड़ी, नि० आसोलियों की मादड़ी, तह०
तहसील मावली व अन्य मावली, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....10 / 2020.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
..... मावली मुकाम.....मुखर्षे.....15.....माह.....11.....2019

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....09.....माह.....11.....सन् 2020 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री तुलसीराम डांगी.....मिनजानिब अपीलान्त वश्री मनीष शर्मा
.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि..... अपील अपीलान्त
सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री
दिनांक 15-11-2019 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....09.....माह.....11.....2020
को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू०	पै०	रेस्पोंडेन्ट	रू०	पै०
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।